राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

(1) डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 986/2022

1. महेंद्र कुमार जाट पुत्र श्री कल्याण मल, उम्र लगभग उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम अकोदिया, पोस्ट संथली, तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
2. लक्ष्मण फरोदा पुत्र श्री राम निवास, उम्र लगभग 25 वर्ष साल, निवासी मुखियाबास, गांव गाजू, जिला नागौर (राज.)
3. कुलदीप शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम डोबला खुर्द पोस्ट गांगल्यावास, तहसील रामगढ, पचवारा, जिला दौसा (राज.)
4. मनीष कुमार नागर पुत्र श्री धनराज नागर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट कटावर तहसील अटरू, जिला बारां (राज.)
5. नरेन्द्र मेघवाल पुत्र श्री नाना लाल, उम्र लगभग 35 वर्ष साल, निवासी 11/112, नाकोड़ा नगर, धूलजी की बावरी, देबारी रोड, जिला उदयपुर (राज.)
6. हेत राम गोदारा पुत्र श्री रुघा राम गोदारा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट सुरनाणा, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राज.)

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव राजस्व विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. कपिल कुमार शर्मा, श्री महेश चंद शर्मा के पुत्र,उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम डांगरवाड़ा पोस्ट श्रीचंदपुरा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर (राज.)
5. मनोज कुमार डागुर पुत्र श्री विजय सिंह डागुर, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट खेड़ीहैवत, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज.)
6. हरिओम सिंह गुर्जर पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गुर्जर,उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम मुरलीपुरा, पोस्टपंचोली, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राज.)
7. कल्पित शर्मा, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट कोलानाबांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा (राज.)

8. लाल चंद जाखड़ पुत्र श्री गणपत राम, लगभग उम्र 32 वर्ष, निवासी 182, वार्ड क्रमांक 03, मंदिर की ग्वार,तेजरासर, बीकानेर (राज.)

9. मनीष कुमार सेजू पुत्र श्री जगजीवन राम, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी संधवा, फतेहगढ़, जिला जैसलमेर (राज.)

10. कन्हैया लाल चौधरी पुत्र श्री राज लाल चौधरी, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी गांव खलीलपुरा पापरा, पोस्ट बामोर, जिला टोंक (राज.)

11. मनफूल सिंह सारण पुत्र श्री जीत राम सारण,उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी चक-39, एलएनपी कॉलोनी, पी.ओ. बैंजबायला, तेशिल पदमपुर, जिला श्री गंगानगर (राज.)

12. प्रवीण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र लगभग 25 वर्ष साल, निवासी ग्राम ढाणी पूनिया, पोस्ट झाड़सर छोटा, तहसील तारानगर, जिला चूरू (राज.)

13. प्रकाश जांदू पुत्र श्री बक्शा राम, उम्र लगभग 25 वर्ष वर्ष, जनेवा पूर्व, ग्राम व पोस्ट जनेवा के निवासी पूर्व, जिला नागौर (राज.)

14. कैलाश पुत्र श्री राजूराम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट फररोड, तहसील जायल, जिला नागौर (राज.)

15. नीलेश कटारा पुत्र श्री वरसिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, ग्राम कुशलीपाड़ा, पोस्ट जालिमपुरा, तहसील के निवासी सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

----प्रतिवादीगण

साथ

(2) डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 782/2022

1. प्रकाश विश्नोई पुत्र श्री पुखराज, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी विश्नोईयों का बास, बीसलपुर, जिला जोधपुर (राजस्थान)

2. कृष्णकान्त शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, वृद्ध लगभग 29 वर्ष, निवासी विरहटा, खुंडा, जिला करौली (राजस्थान)

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव राजस्व विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।

3. अध्यक्ष, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।

4. प्रेमा राम पुत्र श्री शंकर राम, उम्र लगभग 25 वर्ष साल, निवासी जाणियों की ढाणियाँ, रामसर, कर्णू, जिला नागौर (राजस्थान)

5. महेंद्र सिंह पुत्र श्री डोला राम, उम्र लगभग 23 वर्ष साल, निवासी कमेड़िया का बास, खेड़ा किशनपुरा, जिला नागौर (राजस्थान)

6. आशीष कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी देवनगर, बानसूर, अलवर (राजस्थान)

7. हेमाराम पुत्र श्री बजरंग लाल, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी शेखपुरा, रियान बड़ी, जिला नागौर (राजस्थान)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री जे.एम. सक्सेना, अधिवक्ता, श्री संजीव कुमार सिंघल, अधिवक्ता, श्री विशाल राज मेहता, अधिवक्ता और सुश्री वंदना, अधिवक्ता, श्री चैतन्य कुमार गहलोत, अधिवक्ता की ओर से वी.सी. के माध्यम से
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री नलिन जी. नारायण, अधिवक्ता श्री राजेश महर्षि, एएजी श्री उदित शर्मा, अधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल, एएजी वीसी द्वारा श्री विनित सनाढ्य, अधिवक्ता वीसी के माध्यम से श्री तनंजय परमार, अधिवक्ता वीसी के माध्यम से

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

(वी सी के माध्यम से)

निर्णय

निर्णय सुनाया गया : 10/07/2024

रिपोर्ट करने योग्य

प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश

1. यह आदेश उपरोक्त दो अंतरन्यायालयीय अपीलों के निपटान को नियंत्रित करेगा।

2. डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 782/2022, जो इस न्यायालय की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में दायर की गई है, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका सहित रिट याचिकाओं के एक समूह में पारित दिनांक 27.05.2022 के एक सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई है। डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 986/2022, जो जयपुर पीठ, जयपुर में दायर की गई है, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका सहित रिट याचिकाओं के एक समूह में पारित दिनांक 19.07.2022 के एक सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई है।

3. दोनों अपीलों की सुनवाई जयपुर पीठ, जयपुर में समान रूप से की गई।

4. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा) द्वारा दिनांक 17.01.2020 को पटवारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया गया था। प्रतियोगी लिखित परीक्षा दिनांक 23.10.2021 को आयोजित की गई थी और बोर्ड द्वारा दिनांक 23.10.2021 को ही प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर प्रारंभिक उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित उत्तर कुंजी के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के निर्णय के आधार पर दिनांक 25.01.2022 को बोर्ड द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई। इसके बाद चयन सूची का प्रकाशन किया गया।

5. इस स्तर पर, अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ताओं ने जोधपुर में मुख्य पीठ के साथ-साथ जयपुर पीठ में भी अपनी-अपनी रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिसमें विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्तर कुंजी की शुद्धता के संबंध में लिए गए निर्णय पर सवाल उठाया गया, जैसा कि विशेषज्ञ समिति द्वारा तय किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने जोधपुर में मुख्य पीठ में दायर रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते हुए, दिनांक 27.05.2022 के आदेश के तहत विभिन्न प्रश्नों की उत्तर कुंजी की शुद्धता से संबंधित मुद्दे की जाँच की। यह निष्कर्ष निकला कि प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला-104 डी के

प्रश्न संख्या 69 और 98 को छोड़कर, जिसमें प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला-104 डी के प्रश्न संख्या 98 के लिए, बोर्ड द्वारा रियायत के आधार पर, उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई कोई भी आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित हस्तक्षेप के मापदंडों के अंतर्गत नहीं आती है और इसलिए, माना जाता है कि दो प्रश्नों को छोड़कर, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई। हालांकि, अपीलकर्ता- प्रकाश विश्नोई और एक अन्य (डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 782/2022), प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला-104 सी के प्रश्न संख्या 135 की उत्तर कुंजी की शुद्धता के संबंध में आदेश से व्यथित महसूस करते हैं और उन्होंने अंतर-न्यायालय अपील दायर की।

6. चूंकि अपीलकर्ता महेंद्र कुमार जाट की रिट याचिका (डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 986/2022) और अन्य याचिकाओं सहित याचिकाओं के बैच को जयपुर बेंच, जयपुर में एकल पीठ द्वारा दिनांक 19.07.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए समान मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं के एक अन्य बैच में जोधपुर में मुख्य सीट पर एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में, यह अपील भी महेंद्र कुमार जाट द्वारा पेश की गई है।

7. दोनों अपीलों में, इस न्यायालय के विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कि प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला-104 सी के प्रश्न संख्या 135 की सही उत्तर कुंजी के संबंध में विशेषज्ञ समिति का निर्णय हस्तक्षेप का हकदार है। दोनों अपीलों में पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा बहस के दौरान कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

8. प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला-104C का प्रश्न संख्या 135 इस प्रकार है:-

"135. संत पीपा की गुफा कहां है?

(A) पीपाड़ (B) टोडा

(C) धनेरा (D) गागरोन"

9. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जब बोर्ड द्वारा प्रारंभिक उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी, तो विकल्प "(बी) टोडा" को सही उत्तर कुंजी के रूप में चिह्नित किया गया था। हालाँकि, जब विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा उत्तर कुंजी की शुद्धता के संबंध में आपत्तियाँ की गईं, जिन्होंने दावा किया कि सही उत्तर कुंजी विकल्प "(डी) गगरोन" थी, तो बोर्ड ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की और प्रश्न संख्या 135 के संबंध में इस आपत्ति को अन्य प्रश्नों की उत्तर कुंजी की शुद्धता पर आपत्ति के साथ संदर्भित किया। यह भी विवाद में नहीं है कि विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न आपत्तियों

पर विचार करने के बाद उत्तर कुंजी को विकल्प “(बी) टोडा” से बदलकर विकल्प “(डी) गगरोन” कर दिया।

10. अपीलकर्ता प्रकाश विश्नोई और अन्य के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेषज्ञ समिति के दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए आपत्तियों को खारिज कर दिया। इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

> “**<u>विशेषज्ञ समिति का दृष्टिकोण</u>**: विशेषज्ञ समिति ने डॉ. हुकमचंद जैन और नारायण माली द्वारा लिखित **राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10** और **राजस्थान–इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लापीडिया** का संदर्भ लेते हुए निष्कर्ष निकाला कि सही उत्तर (डी) है।
>
> यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में कुछ सामग्री भी रिकॉर्ड पर रखी है कि उत्तर “बी” सही है, हालांकि, विशेषज्ञ समिति ने सामग्री पर विचार करने के बाद, जैसा कि पहले यहां उल्लेख किया गया है, और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री, एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंची है, इस न्यायालय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करने का कोई कारण नहीं है।”

11. दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने समान दलीलें पेश कीं। अभिलेख पर प्रस्तुत विभिन्न सामग्रियों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया है कि जब विभिन्न प्रामाणिक ग्रंथों में दर्ज है कि संत पीपा की गुफा टोडा में थी, तो विशेषज्ञों की समिति ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी प्रामाणिक सामग्री/ग्रंथ के इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि संत पीपा की गुफा गागरोन में स्थित है।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यद्यपि प्रारंभ में "टोडा" को सही उत्तर कुंजी के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन जब विभिन्न आपत्तियां उठाई गईं और कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि संत पीपा की गुफा गागरोन में है, तो मामले को विशेषज्ञों की समिति को भेजा गया और विशेषज्ञों की समिति ने विभिन्न ग्रंथों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंततः निष्कर्ष निकाला कि विकल्प "(डी) गागरोन" को सही उत्तर कुंजी माना जाना चाहिए।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है।

14. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि यद्यपि न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है, फिर भी वर्तमान में ऐसा मामला है, जिसमें विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत है, जो अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए विभिन्न ग्रंथों, सूचनाओं और सामग्रियों की विषय-वस्तु से परिलक्षित होता है।

प्रतिवादियों के विद्वान वकील का कहना है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित है और इस न्यायालय को पुनर्मूल्यांकन की कोई कवायद नहीं करनी चाहिए, और न ही किसी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, इस बारे में अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए, सिवाय बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, जहां युक्तिकरण की किसी विस्तृत प्रक्रिया के बिना, उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत साबित हो जाती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में निर्धारित किया है।

15. मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने से पहले, प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर कुंजी की सत्यता को चुनौती देने के मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में इस मुद्दे पर प्रसिद्ध निर्णयों का संदर्भ लेना उपयोगी होगा।

16. सबसे पहले, यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन कानून में स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि कई निर्णयों में माना गया है।

17. इस संबंध में स्थापित कानूनी स्थिति को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर और अन्य, (2010) 6 एससीसी 759 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया था और इसे निम्नानुसार माना गया था: -

> "24. उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का मुद्दा अब एकीकृत नहीं रह गया है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम पारितोष भूपेश कूर्मरशेठ मामले में विस्तार से विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में न्यायालय द्वारा इस आशय का निर्देश जारी किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि नियमों/विनियमों में शामिल नीतिगत निर्णय को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसमें पुनर्जांच/ सत्यापन/

पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, जब तक कि यह दिखाने के लिए आधार न हों कि नीति स्वयं किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना: (एससीसी पृष्ठ 39-40 और 42, पैरा 14 और 16)

"14...नीति के तौर पर यह तय करना पूरी तरह से विधानमंडल और उसके प्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में है कि कानून के प्रावधानों को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है और अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए नियमों या विनियमों में कौन से उपाय, मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक शामिल किए जाने चाहिए...

16...न्यायालय विधानमंडल और अधीनस्थ विनियमन-निर्माण निकाय द्वारा विकसित नीति की बुद्धिमत्ता पर निर्णय नहीं ले सकता। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति हो सकती है जो अधिनियम के उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावी बनाएगी या इसमें प्रभावशीलता की कमी हो सकती है और इसलिए संशोधन और सुधार की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन किसी नियम या विनियमन में शामिल नीति में कोई भी कमी उसे अधिकारहीन नहीं बनाती और न्यायालय उसे इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि उसकी राय में यह कोई बुद्धिमानी या विवेकपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि मूर्खतापूर्ण है और यह वास्तव में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी...."

25. इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग में अनुमोदित किया है और इस पर भरोसा किया है तथा इसे दोहराया है, जिसमें निम्नांकित टिप्पणी की गई है: (एससीसी पृ. 717-18, पैरा 7)

"7.... आयोग के सुसंगत नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अंतर्गत कोई अभ्यर्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का हकदार हो। केवल जांच का प्रावधान है, जिसमें उत्तर-पुस्तिकाओं को इस उद्देश्य से देखा जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की जांच की गई है या नहीं और प्रत्येक प्रश्न के अंकों के योग में कोई गलती हुई है या नहीं तथा उन्हें उत्तर-पुस्तिका के प्रथम कवर

पृष्ठ पर सही ढंग से अंकित किया गया है या नहीं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जांच के पश्चात अपीलकर्ता को सामान्य विज्ञान के पेपर में दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं पाई गई। प्रासंगिक नियमों में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण, किसी भी परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

(जोर दिया गया)

मुनीब उल रहमान हारून (डॉ.) बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम डी. सुवनकर, पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अयान दास और साहिती बनाम डॉ. एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में भी इसी तरह का दृष्टिकोण दोहराया गया है।

26. इस प्रकार, इस विषय पर कानून इस प्रकार उभर कर आता है कि कानून या वैधानिक नियमों/विनियमों के तहत किसी प्रावधान के अभाव में, न्यायालय को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।

18. रण विजय सिंह एवं अन्य (उपरोक्त) तथा त्रिपुरा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी एवं अन्य, (2019) 16 एससीसी 663 के माध्यम से मामलों में उक्त कानूनी स्थिति की पुनः पुष्टि की गई है।

19. हालांकि, एक ऐसी स्थिति जहां मुख्य उत्तर स्वयं गलत पाए जाते हैं, जिसके लिए आवश्यक सुधार की आवश्यकता होती है, पर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है।

कानपुर विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति एवं अन्य (उपरोक्त) के माध्यम से कुछ प्रश्नों के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ कि उन प्रश्नों के मुख्य उत्तर सही नहीं थे। तथ्यों के आधार पर, प्रामाणिक ग्रंथों की जांच करने पर, यह माना गया कि मुख्य उत्तर स्वयं सही नहीं थे। उच्च न्यायालय ने विशेष प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश जारी किए। ऐसे निर्देश की पुष्टि की गई। यह माना गया कि यदि संदेह का मामला है, तो पहले से दिए गए मुख्य उत्तरों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन यदि मामला संदेह के दायरे से परे है, तो छात्रों को गलत साबित

हुए मुख्य उत्तर के अनुरूप उत्तर न देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा। यह महत्वपूर्ण रूप से देखा गया:-

> "15. उच्च न्यायालय के निष्कर्षों ने छात्र समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आम तौर पर, कोई भी व्यक्ति, खासकर यदि वह पेपर सेटर और परीक्षक रहा हो, इस दृष्टिकोण से इच्छुक होगा कि प्रस्तुत मुख्य उत्तर पेपर सेटर है और विश्वविद्यालय द्वारा सही माना जाता है, उसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे प्राप्त करने का एक तरीका मुख्य उत्तर को प्रकाशित ही न करना है। यदि विश्वविद्यालय ने परीक्षा के परिणाम के साथ मुख्य उत्तर प्रकाशित नहीं किया होता, तो इस मामले में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यह उन मामलों को देखने का सही तरीका नहीं है, जिनमें सैकड़ों छात्रों का भविष्य शामिल है, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं। यदि इस मामले में मुख्य उत्तर को गुप्त रखा जाता, तो उपाय बीमारी से भी बदतर होता, क्योंकि बहुत से छात्रों को चुपचाप अन्याय सहना पड़ता। मुख्य उत्तर के प्रकाशन ने एक दुखद स्थिति को उजागर किया है जिसका समाधान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को खोजना होगा। मुख्य उत्तर प्रकाशित करने में उनकी निष्पक्षता की भावना ने उन्हें अपने द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली पर करीब से नज़र डालने का अवसर दिया है। जो विफल हुआ है वह कंप्यूटर नहीं बल्कि मानव प्रणाली है।
>
> 16. श्री कक्कड़, जो विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित हुए, ने तर्क दिया कि किसी मुख्य उत्तर की सत्यता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि वह प्रथम दृष्टया गलत न हो। हम इस बात से सहमत हैं कि मुख्य उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि वह गलत साबित न हो जाए और यह कि इसे तर्क की अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से गलत साबित होना चाहिए, यानी यह ऐसा होना चाहिए कि किसी विशेष विषय में पारंगत कोई भी उचित व्यक्ति इसे सही न माने। इस मामले में विश्वविद्यालय का तर्क बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों द्वारा गलत साबित होता है, जिन्हें उत्तर प्रदेश में छात्र आमतौर पर पढ़ते हैं। उन पाठ्यपुस्तकों में इस

बात पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और मुख्य उत्तर गलत है।

17. इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ पुस्तकें निर्धारित की गई हैं और छात्रों को विषयों का जो ज्ञान है, वह उन पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी से प्राप्त होता है। वे पाठ्यपुस्तकें छात्रों के मामले का पूर्ण समर्थन करती हैं। यदि यह संदेह का मामला होता, तो हम निस्संदेह मुख्य उत्तर को प्राथमिकता देते। लेकिन यदि मामला संदेह के दायरे से परे है, तो छात्रों को मुख्य उत्तर के अनुरूप उत्तर न देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा, अर्थात ऐसा उत्तर देना जो गलत साबित हो गया हो।

20. मनीष उज्ज्वल एवं अन्य बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय एवं अन्य, (2005) 13 एससीसी 744 के एक अन्य मामले में भी इसी तरह की चुनौती दी गई थी, जिसमें छात्र समुदाय ने मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में रैंकिंग को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि जिन प्रमुख उत्तरों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था, वे स्वयं गलत थे और परिणामस्वरूप गलत और त्रुटिपूर्ण रैंकिंग तैयार की गई थी।

21. विशेषज्ञों की राय मांगी गई थी। विशेषज्ञों की राय एकमत थी कि विवादित प्रश्नों के प्रमुख उत्तर त्रुटिपूर्ण थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"8. xxxxxxxxxxxx. यह संभव है कि छह प्रश्नों के सही कुंजी उत्तरों को भरने से नए मूल्यांकन से उन लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिन्होंने इन प्रश्नों के संबंध में गलत कुंजी भरने से घोषित परिणामों और रैंकिंग के आधार पर पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है। हालांकि हमारा मानना है कि विशेष रूप से अपीलकर्ताओं और सामान्य रूप से छात्र समुदाय, चाहे किसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं, को स्पष्ट रूप से गलत कुंजी उत्तरों के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए, लेकिन साथ ही, यदि पहले काउंसलिंग के परिणामस्वरूप पहले से दिए गए प्रवेश बाधित होते

हैं, तो यह संभव है कि पाठ्यक्रम की शुरुआत में देरी हो सकती है और पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30-09-2005 से आगे बढ़ सकती है, जो कि विनियमों में समय सारिणी के अनुसार और मृदुल धर (माइनर) बनाम भारत संघ में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार कट-ऑफ तिथि है। इस दृष्टिकोण से, हम यह स्पष्ट करते हैं कि सही मुख्य उत्तरों को फीड करके पेपरों का नया मूल्यांकन उन छात्रों को प्रभावित नहीं करेगा, जिन्होंने पहले घोषित परिणामों के संदर्भ में दी गई रैंकिंग के आधार पर पहली काउंसलिंग के परिणामस्वरूप प्रवेश प्राप्त किया है।

यह देखते हुए कि मामला छात्रों के प्रवेश से संबंधित है और कई प्रवेश पहले ही दिए जा चुके हैं, उस मामले के विशिष्ट तथ्यों में यह स्पष्ट किया गया कि सही उत्तरों को दर्ज करके पेपरों का नए सिरे से मूल्यांकन करने से उन छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन्होंने पहले से घोषित परिणामों के संदर्भ में दी गई रैंकिंग के आधार पर पहली काउंसलिंग के परिणामस्वरूप प्रवेश प्राप्त किया है। हालांकि, विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा विवादित प्रमुख उत्तरों की जांच करने के अभ्यास को बरकरार रखा गया।

22. कुलपति और अन्य (उपरोक्त) के माध्यम से कानपुर विश्वविद्यालय के मामले में निर्णय पर भी भरोसा किया गया, सिद्धांत को ऊपर के रूप में दोहराया गया और मनीष उज्ज्वल और अन्य (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमेय कार्रवाई को दोहराया गया: -

> "9. कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता में इसी तरह की समस्या पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि मुख्य उत्तरों के सही होने के बारे में एक धारणा है और संदेह की स्थिति में, न्यायालय निस्संदेह मुख्य उत्तर को प्राथमिकता देगा। इसी कारण से हमने उन मुख्य उत्तरों का उल्लेख नहीं किया है जिनके बारे में विशेषज्ञों के बीच मतभेद के परिणामस्वरूप संदेह है। मुख्य उत्तरों के बारे में, जिनके बारे में मामला संदेह के दायरे से परे है, इस न्यायालय ने माना है कि मुख्य उत्तर के अनुरूप उत्तर न देने के लिए छात्रों को दंडित करना अनुचित होगा, अर्थात ऐसा उत्तर जो गलत साबित हो चुका है। उपरोक्त छह मुख्य उत्तरों के स्पष्ट रूप से गलत होने के बारे में कोई विवाद नहीं है और विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा इस तथ्य पर सवाल नहीं

उठाया गया है। इस दृष्टिकोण से, छात्रों को विश्वविद्यालय की गलती और लापरवाही के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।"

रण विजय सिंह एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में बाद में लिए गए निर्णय में, इस विषय पर कानून का सारांश इस प्रकार दिया गया:-

"30. इसलिए, इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करने का प्रस्ताव करते हैं। वे हैं:

30.1 यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच को अधिकार के रूप में अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी इसकी अनुमति दे सकता है;

30.2 यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (इसे प्रतिबंधित करने से अलग) तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, बिना किसी "तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या तर्कसंगतकरण की प्रक्रिया" के और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में कि कोई भौतिक त्रुटि की गई है;

30.3 न्यायालय को किसी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए-इस मामले में न्यायालय की कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शैक्षणिक लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए;

30.4 न्यायालय को मुख्य उत्तरों की सत्यता को मानकर उसी धारणा के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए; और

30.5 संदेह की स्थिति में, लाभ अभ्यर्थी के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिए।

रजिस्ट्रार जनरल (उपरोक्त) के माध्यम से त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मामले में नवीनतम निर्णयों में से एक में, स्थापित कानूनी स्थिति को दोहराते हुए और

पुनः पुष्टि करते हुए कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है या आदेश नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि पहले कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य (उपरोक्त), मनीष उज्ज्वल और अन्य (उपरोक्त) और रण विजय सिंह और अन्य (उपरोक्त) के माध्यम से देखा गया था, असाधारण प्रकृति के मामलों पर विचार किया गया और ऐसे असाधारण मामलों से निपटने के लिए कार्रवाई का अनुमेय तरीका विकसित किया गया, भले ही पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान न हो।

> "19. हमने इस न्यायालय के निर्णयों पर गौर किया है। निस्संदेह, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्धारित किया है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी प्रावधान के अभाव में पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या माँगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। निस्संदेह, कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने भी उक्त निर्णय में उक्त आधार पर कार्यवाही की है। पहला प्रश्न जिसका हमें उत्तर देना होगा, वह यह है कि क्या किसी प्रावधान के अभाव के बावजूद, न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने के अधिकार के प्रयोग में पूरी तरह से शक्तिहीन हैं? यह सच है कि परमादेश की रिट माँगने का अधिकार कानूनी अधिकार के अस्तित्व और उत्तर देने वाले प्रतिवादी के साथ सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के संगत कर्तव्य पर आधारित है। इस प्रकार, अधिकार के रूप में, यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रतिवादी पुनर्मूल्यांकन की माँग करने वाली रिट याचिका या समीक्षा याचिका को बनाए नहीं रख सकता था।
>
> 20. फिर भी सवाल यह उठता है कि अगर पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं जो न्यायालय को किसी भी तरह के संदेह में छोड़ दें। कुछ परिस्थितियों में रिट आवेदक के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। ऐसा मामला तब भी उठ सकता है जब पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान न होने के बावजूद यह पता चले कि सही उत्तर देने के बावजूद कोई अंक नहीं दिए गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे ऐसे मामले तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जहाँ उत्तर की शुद्धता के बारे में कोई विवाद न

हो। इसके अलावा, अगर कोई संदेह है, तो संदेह का समाधान परीक्षा निकाय के पक्ष में किया जाना चाहिए न कि उम्मीदवार के पक्ष में। अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्ति उपलब्ध रह सकती है, भले ही पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान न हो, ऐसी स्थिति में जब कोई अभ्यर्थी सही उत्तर देने के बावजूद, जिसके बारे में जरा भी संदेह नहीं हो सकता, उसे गलत उत्तर देने वाला माना जाता है और परिणामस्वरूप अभ्यर्थी को किसी भी अंक का हकदार नहीं माना जाता है।

21. यदि रिट न्यायालय के समक्ष दूसरी परिस्थिति उपस्थित हो जाए, तो क्या रिट न्यायालय अपनी शक्तियों के विशाल भण्डार के बावजूद असहाय हो सकता है? यह कहना एक बात है कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान का अभाव अभ्यर्थी को अधिकार के रूप में मूल्यांकन के अधिकार का दावा करने में सक्षम नहीं बनाएगा और यह कहना दूसरी बात है कि किसी भी परिस्थिति में जहां पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, क्या रिट न्यायालय अपनी निस्संदेह संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करेगा? हम दोहराते हैं कि स्थिति केवल दुर्लभ और अपवादस्वरूप हो सकती है।

22. इसलिए हम पैरा 30.2 में निष्कर्ष को समझेंगे जिसे हमने रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय से निकाला है, केवल पूर्वोक्त प्रकाश में। हम पहले ही देख चुके हैं कि एच.पी. लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने पैराग्राफ 26 में पूरे मामले के कानून का सर्वेक्षण करने के बाद यह भी समझा है कि किसी भी प्रावधान के अभाव में न्यायालय को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।

23. xxxxxxxxx. रण विजय सिंह बनाम राहुल सिंह में इस न्यायालय के निर्णय में भी, जो प्रथम प्रतिवादी के अनुसार उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का आधार है, हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है, न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि न्यायालय पुनर्मूल्यांकन की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब यह बिना किसी अनुमानात्मक तर्क प्रक्रिया या युक्तिकरण

की प्रक्रिया के बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में ही भौतिक त्रुटि होने पर। xxxxxxxx।"

23. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मामले में, इसके अध्यक्ष और अन्य बनाम राहुल सिंह और अन्य (उपरोक्त) के माध्यम से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक प्रकृति के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय की सीमा और शक्ति की जांच करते हुए, कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य (उपरोक्त) और रण विजय सिंह और अन्य (उपरोक्त) के माध्यम से मामलों में निर्णयों पर भरोसा करते हुए, नीचे दिए अनुसार माना:

"9. कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता में, यह न्यायालय संयुक्त प्री-मेडिकल टेस्ट से संबंधित एक मामले पर विचार कर रहा था। बेशक, परीक्षा सेटर ने खुद ही मुख्य उत्तर दिए थे और परीक्षक द्वारा दिए गए मुख्य उत्तरों की शुद्धता को नियंत्रित करने या सत्यापित करने के लिए कोई समिति नहीं थी। इस न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि छात्रों ने साबित कर दिया था कि मुख्य उत्तरों में से तीन गलत थे। न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं:

"16 ..... हम सहमत हैं कि मुख्य उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए और इसे तर्क की अनुमानात्मक प्रक्रिया या तर्कसंगतकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए, यानी यह ऐसा होना चाहिए कि किसी विशेष विषय में पारंगत लोगों का कोई भी उचित समूह इसे सही न माने।"

न्यायालय ने आगे भी निर्देश दिए लेकिन हम मुख्य रूप से इस बात से चिंतित हैं कि राज्य सरकार को प्रश्नपत्र तैयार करने वालों द्वारा दिए गए मुख्य उत्तरों को मॉडरेट करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

10. रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय ने न्यायिक घोषणाओं की एक श्रृंखला का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित शब्दों में कानूनी स्थिति का सारांश दिया: (एससीसी पृष्ठ 368-69, पैरा 30)

"30. इसलिए, इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करने का प्रस्ताव करते हैं। वे हैं:

30.1. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच के अधिकार के रूप में अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी इसकी अनुमति दे सकता है;

30.2. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (इसे प्रतिबंधित करने से अलग) तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, बिना किसी "तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या तर्कसंगतकरण की प्रक्रिया" के और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में कि कोई भौतिक त्रुटि की गई है;

30.3. न्यायालय को किसी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए-इस मामले में न्यायालय की कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शैक्षणिक लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए;

30.4. न्यायालय को मुख्य उत्तरों की सत्यता को मानकर उसी धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए; और

30.5. संदेह की स्थिति में, लाभ अभ्यर्थी के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तब रण विजय सिंह और अन्य (उपरोक्त) के मामले में पैरा 31 और 32 में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया ताकि यह प्रदर्शित और उजागर किया जा सके कि संवैधानिक न्यायालयों को ऐसे मामलों में संयम क्यों बरतना चाहिए और नीचे दिए अनुसार माना:

"11. हम पैरा 31 और 32 में निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं जो दर्शाती हैं कि संवैधानिक न्यायालयों को ऐसे मामलों में संयम क्यों बरतना चाहिए: (रण विजय सिंह मामला, एससीसी पृष्ठ 369)

"31. हम अपनी ओर से यह जोड़ सकते हैं कि उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने या न देने के मामले में सहानुभूति या करुणा कोई भूमिका नहीं निभाती है। यदि परीक्षा प्राधिकरण द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, तो उम्मीदवारों का पूरा समूह पीड़ित होता है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया को केवल इसलिए पटरी से नहीं उतारना चाहिए क्योंकि कुछ उम्मीदवार निराश या असंतुष्ट हैं या उन्हें लगता है कि किसी गलत प्रश्न या गलत उत्तर के कारण उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। सभी उम्मीदवार समान रूप से पीड़ित हैं, हालांकि कुछ को अधिक पीड़ा हो सकती है लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता क्योंकि गणितीय सटीकता हमेशा संभव नहीं होती है। इस न्यायालय ने गतिरोध से बाहर निकलने का एक तरीका दिखाया है - संदिग्ध या आपत्तिजनक प्रश्न को बाहर कर दें।

32. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, जिनमें से कुछ पर ऊपर चर्चा की गई है, न्यायालयों द्वारा परीक्षा के परिणामों में हस्तक्षेप किया जाता है। यह परीक्षा अधिकारियों को एक अप्रिय स्थिति में डालता है, जहाँ वे जांच के दायरे में होते हैं, न कि उम्मीदवार। इसके अतिरिक्त, एक विशाल और कभी-कभी लंबी परीक्षा प्रक्रिया अनिश्चितता के माहौल के साथ समाप्त होती है। जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी में बहुत मेहनत करते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षा अधिकारी भी सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित करने के लिए समान रूप से बहुत प्रयास करते हैं। कार्य की विशालता बाद में कुछ चूक को उजागर कर सकती है, लेकिन न्यायालय को परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों में हस्तक्षेप करने से पहले परीक्षा अधिकारियों द्वारा स्थापित आंतरिक जाँच और संतुलन पर विचार करना चाहिए। वर्तमान अपीलें ऐसे हस्तक्षेप के परिणाम का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहां आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षा परिणाम की कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। परीक्षा अधिकारियों के अलावा अभ्यर्थी भी परीक्षा परिणाम की निश्चितता के बारे में असमंजस में रहते हैं - वे उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं; उनके परिणाम को न्यायालय द्वारा अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाएगा या नहीं; उन्हें कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं; और उन्हें भर्ती मिलेगी या नहीं। यह

असंतोषजनक स्थिति किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है और ऐसी अनिश्चितता की स्थिति के परिणामस्वरूप भ्रम की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। इन सबका समग्र और व्यापक प्रभाव यह है कि जनहित प्रभावित होता है।"

अंत में, पिछले निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को इस प्रकार दोहराया गया:

12. कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उम्मीदवार पर न केवल यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि मुख्य उत्तर गलत है, बल्कि यह भी कि यह एक स्पष्ट गलती है जो पूरी तरह से स्पष्ट है और यह दिखाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमानात्मक प्रक्रिया या तर्क की आवश्यकता नहीं है कि मुख्य उत्तर गलत है। संवैधानिक न्यायालयों को ऐसे मामलों में बहुत संयम बरतना चाहिए और मुख्य उत्तरों की शुद्धता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने में अनिच्छुक होना चाहिए। कानपुर विश्वविद्यालय मामले में, न्यायालय ने निम्नलिखित प्रणाली की सिफारिश की:

(1) संयम;

(2) प्रश्नों में अस्पष्टता से बचना;

(3) संदिग्ध प्रश्नों को बाहर करने के लिए तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए और ऐसे प्रश्नों पर कोई अंक नहीं दिए जाने चाहिए।

13. जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, मुख्य उत्तरों की पहली सूची प्रकाशित करने से पहले ही आयोग ने मुख्य उत्तरों को दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा मॉडरेट करवा लिया था। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की गईं और आपत्तियों की पुष्टि के लिए 26 सदस्यीय समिति गठित की गई और इस अभ्यास के बाद समिति ने सिफारिश की कि 5 प्रश्नों को हटा दिया जाए और 2 प्रश्नों में मुख्य उत्तर बदल दिए जाएं। यह माना जा सकता है कि इन समितियों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल थे जिनके लिए परीक्षार्थियों की परीक्षा ली गई थी। न्यायाधीश अकादमिक मामलों में विशेषज्ञों की भूमिका नहीं निभा सकते। जब तक कि उम्मीदवार यह प्रदर्शित नहीं करता कि मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से गलत हैं, तब तक अदालतें अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकतीं, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के पक्ष और विपक्ष को तौल नहीं सकतीं और फिर

इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकतीं कि कौन सा उत्तर बेहतर या अधिक सही है।

इसके अलावा यह भी पाया गया कि चुनौती तीन सवालों से संबंधित थी, जिन पर तर्क करने की लंबी प्रक्रिया थी और यह भी पाया गया कि आयोग द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन कुछ पाठ्य पुस्तकों द्वारा किया गया था। उस तथ्यात्मक परिदृश्य में, यह माना गया कि परस्पर विरोधी विचारों के मामले में, न्यायालय को विशेषज्ञों की राय के आगे झुकना चाहिए। इसे इस प्रकार माना गया:

> "14. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि तीनों प्रश्नों के लिए तर्क की एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता थी और उच्च न्यायालय ने स्वयं देखा है कि आयोग के रुख का समर्थन कुछ पाठ्यपुस्तकों द्वारा भी किया गया है। जब परस्पर विरोधी विचार हों, तो न्यायालय को विशेषज्ञों की राय के आगे झुकना चाहिए। न्यायाधीश सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ नहीं होते और न ही हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बहुत संयम बरतना चाहिए और विशेषज्ञों की राय को परेशान करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।"

24. रिचल और अन्य (उपरोक्त) के मामले में, अंतिम मुख्य उत्तरों की शुद्धता से निपटने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार बताए गए और दोहराए गए सिद्धांतों की पुष्टि की गई, जैसा कि विशेषज्ञ समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद तय किया गया था। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य (उपरोक्त), मनीष उज्ज्वल एवं अन्य (उपरोक्त) के माध्यम से मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग एवं अन्य (2005) 13 एससीसी 749 और राजेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2013) 4 एससीसी 690 के मामलों में अपने पहले के निर्णयों पर भी भरोसा किया और नीचे दिए अनुसार निर्णय दिया:

> "17. इसी प्रभाव के लिए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग में इस न्यायालय ने विश्वविद्यालय को सीबीएसई द्वारा दिए गए प्रमुख उत्तरों के संदर्भ में 8 प्रश्नों के उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था। इस न्यायालय ने विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम को भी अस्वीकृत कर

दिया, जिसने प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों को अंक दिए, भले ही किसी ने प्रश्नों के उत्तर दिए हों या नहीं।

18. एक अन्य निर्णय जिसका उल्लेख किया गया है वह है राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य, जहां इस न्यायालय को गलत उत्तर कुंजी का उपयोग करके गलत मूल्यांकन से संबंधित मामले पर विचार करने का अवसर मिला था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। चयन प्रक्रिया में लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा शामिल थी। असफल उम्मीदवारों ने चयन का विरोध किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने "मॉडल उत्तर कुंजी" को विशेषज्ञों को संदर्भित किया। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर, एकल न्यायाधीश ने माना कि 100 में से 41 मॉडल उत्तर गलत हैं। एकल न्यायाधीश ने माना कि पूरी परीक्षा रद्द करने योग्य थी और इसके आधार पर की गई नियुक्तियाँ भी रद्द की जानी चाहिए। कुछ उम्मीदवारों द्वारा लेटर पेटेंट अपील दायर की गई थी जिसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आंशिक रूप से अनुमति दी थी। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया और घोषणा की कि पूरी परीक्षा रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 19 में कहा था: (एससीसी पृष्ठ 697)

"19. श्री राव द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क बिना योग्यता के नहीं हैं। उत्तर कुंजी में दोष की प्रकृति को देखते हुए, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को सही करने का सबसे स्वाभाविक और तार्किक तरीका उत्तर कुंजी को सही करना और उसके आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाना था। ऐसी परिस्थितियों में, आयोग द्वारा नई परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं था, खासकर जब किसी भी तरह के कदाचार, धोखाधड़ी या भ्रष्ट इरादों के बारे में कोई आरोप नहीं था जो संभवतः पिछली परीक्षा को दूषित कर सकता था और सभी संबंधितों द्वारा नए सिरे से प्रयास करने के लिए कहा जा सकता था। सही कुंजी के संदर्भ में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया कम खर्चीली होने के अलावा तेज भी होगी। इस प्रक्रिया से

पहले आयोजित परीक्षा और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आयोजित की गई परीक्षा के बीच समय अंतराल के कारण किसी भी उम्मीदवार को कोई अनुचित लाभ नहीं मिलेगा। यह कहना पर्याप्त है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन एक बेहतर विकल्प था और है।"

यह मानते हुए कि प्रश्नपत्र तैयार करने वाले या जांच करने वाले निकाय द्वारा तैयार किए गए मुख्य उत्तरों को उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया माना जाता है, मुख्य उत्तरों का प्रकाशन और जांच करने वाले निकाय द्वारा विचार किए जाने वाले आपत्तियों को प्राप्त करके उत्तरों की शुद्धता का आकलन करने का अवसर प्रदान करना पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए एक कदम माना गया। यह इस प्रकार देखा गया:

"19. पेपर-सेटर या जांच करने वाली संस्था द्वारा तैयार किए गए मुख्य उत्तरों को उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया माना जाता है। गलती करना मानवीय स्वभाव है। ऐसे कई कारक हैं जो गलत मुख्य उत्तरों को तैयार करने का कारण बन सकते हैं। मुख्य उत्तरों का प्रकाशन पारदर्शिता प्राप्त करने और उम्मीदवारों को उनके उत्तरों की शुद्धता का आकलन करने का अवसर देने के लिए एक कदम है। जांच करने वाली संस्था द्वारा अपलोड किए गए मुख्य उत्तरों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का अवसर प्रक्रिया में निष्पक्षता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक कदम है। मुख्य उत्तरों पर आपत्तियों की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जानी चाहिए और उसके बाद सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, जांच करने वाली संस्था द्वारा किए जाने चाहिए। वर्तमान मामले में, हमने देखा है कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद आयोग द्वारा अंतिम मुख्य उत्तर प्रकाशित किए गए थे, उसके बाद आयोग द्वारा अपनाए गए मुख्य उत्तरों की शुद्धता को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञों के विचारों को स्वीकार करते हुए चुनौती को खारिज कर दिया। अभ्यर्थी अभी भी असंतुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने ये अपीलें दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।"

25. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों और निर्धारित कानूनी स्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य बनाम

अरुण कुमार एवं अन्य, (2020) 6 एससीसी 362 और विकेश कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2021) 2 एससीसी 309 के मामलों में हाल ही में दिए गए न्यायिक निर्णयों में दोहराया है। विकेश कुमार गुप्ता एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में एक बार फिर रण विजय सिंह एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया। निम्नानुसार टिप्पणी की गईः

> 16. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून के मद्देनजर, डिवीजन बेंच के लिए यह खुला नहीं था कि वह प्रश्नों और उत्तर कुंजी की सत्यता की जांच करे और 12.03.2019 के अपने फैसले में विशेषज्ञ समिति के फैसले से अलग निष्कर्ष पर पहुंचे। अपीलकर्ताओं ने रिचल बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग पर भरोसा किया। उक्त फैसले में, इस न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति की राय प्राप्त करने के बाद ही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, लेकिन प्रश्नों और उत्तरों की सत्यता पर स्वयं विचार नहीं किया। इसलिए, उक्त निर्णय इस मामले में विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है।

26. उपर्युक्त निर्णयों के मद्देनजर, यह स्थापित कानूनी स्थिति के रूप में उभर कर आता है कि हालांकि परीक्षा को नियंत्रित करने वाले किसी नियम/योजना के अभाव में पुनर्मूल्यांकन कानून में अनुमेय नहीं है, लेकिन अपवादस्वरूप मामलों में, जहां उत्तर स्पष्ट रूप से गलत पाए जाते हैं, उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। ऊपर संदर्भित कई मामलों में अपनाई गई कार्यवाही, जिसे न्यायालयों ने मंजूरी दी थी, यह थी कि मुख्य उत्तरों या विवादित प्रश्नों के संबंध में शिकायतों की विशेषज्ञों की समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए और यदि विशेषज्ञों की समिति की राय दर्शाती है कि मॉडल उत्तर स्पष्ट रूप से गलत हैं और कोई अन्य विकल्प सही है, तो उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों का सही मुख्य उत्तर के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। जहां प्रश्न स्वयं अस्पष्ट और गलत थे या जहां दिए गए विकल्पों में से कई सही उत्तरों का मामला है, वहां प्रश्नों को हटा दिया जाना चाहिए और उम्मीदवारों का मूल्यांकन हटाए जाने के बाद शेष प्रश्नों के उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का दायरा उन अपवादात्मक मामलों तक सीमित है, जहां न्यायालय पाता है कि मॉडल उत्तर कुंजियाँ तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया को शामिल किए बिना स्पष्ट रूप से गलत हैं।

27. अब हम उपरोक्त कानूनी स्थिति के प्रकाश में मामले के तथ्यों की जांच करेंगे।

28. अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित सामग्रियों पर भरोसा किया है:-

(i) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, टोडारायसिंह का पत्र दिनांक 04.05.2022, जिसमें कुशाल भारद्वाज के आवेदन पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की गई है कि संत पीपा जी की गुफा बुद्ध सागर तालाब, टोडारायसिंह की पहाड़ियों पर स्थित है।

(ii) उपाध्यक्ष, नगर पालिका, टोडारायसिंह, टोंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत फोटोग्राफ दर्शाते हैं कि संत पीपा की गुफा टोडारायसिंह, टोंक में बुद्ध सागर तालाब की पहाड़ियों पर स्थित है।

(iii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर सर्कल की वेबसाइट सामग्री, जिसमें दर्शाया गया है कि पीपा जी मंदिर टोडारायसिंह में स्थित है।

(iv) डॉ. हुकम चंद जैन एवं डॉ. नारायण माली द्वारा लिखित पाठ्यपुस्तक **राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया** के पृष्ठ 532, जिस पर विशेषज्ञों की समिति ने भरोसा जताया है, में स्वयं उल्लेख है कि पीपा जी की गुफा टोडारायसिंह में स्थित है।

(v) ललित शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक **राजस्थान राजर्षि संत पीपाजी** में उल्लेख है कि संत पीपा जी ने टोडा नगर में बुद्ध सागर सरोवर पहाड़ियों में एक गुफा का निर्माण कराया था।

(vi) कार्यकारी अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए 2008 में आयोजित एक पूर्व परीक्षा में भी सही उत्तर कुंजी "टोडा" के रूप में स्वीकार की गई थी, न कि "गागरोन" के रूप में, जहां संत पीपा की गुफा स्थित है।

29. विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेषज्ञ समिति के निर्णय को बरकरार रखा, यह ध्यान में रखते हुए कि विशेषज्ञ समिति ने अपने पास उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि सही उत्तर कुंजी विकल्प (डी) होगी, अर्थात गागरोन वह स्थान है जहां संत पीपा जी की गुफा स्थित है।

30. प्रश्न संख्या 135 की सही उत्तर कुंजी पर निर्णय के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। समिति के समक्ष निम्नलिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई:-

"विकल्प बी गलत है तथा विकल्प डी सही है। राजस्थान का इतिहास संस्कृति परम्परा एवं विरासत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार डॉ. हुकम चंद जैन एवं डॉ. नारायण लाल माली संस्करण 2020 पृष्ठ संख्या 373 तथा क्षितिज कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पृष्ठ संख्या 102 कृपया इस प्रश्न पर विचार करें तथा मुझे बोनस अंक प्रदान करें।"

समिति ने निम्नानुसार निर्णय लिया:-

"आपत्ति स्वीकार की गई" - "प्रमाण संलग्न करें- **राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया, डा. हुकुम चन्द जैन, डा॰ नारायण माली. P.196"**

31. तदनुसार समिति ने आपत्ति स्वीकार कर ली और विकल्प "(डी) गागरोन" को सही उत्तर कुंजी के रूप में अंतिम रूप दिया। विचार चार्ट के अंतिम कॉलम से पता चलता है कि समिति ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए डॉ. हुकम चंद जैन और डॉ. नारायण माली द्वारा लिखित पुस्तक **राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया** (पृष्ठ-196) की सामग्री पर भरोसा किया है। सीलबंद लिफाफे में विशेषज्ञ समिति द्वारा भरोसा किए गए उपरोक्त पाठ/विश्वकोश के प्रासंगिक अंश शामिल हैं। प्रासंगिक सामग्री इस प्रकार है:-

"संत पीपा गागरोन के खींची राजपूत राजा थे। इनका राज्यकाल 1362 से 1377 ई. तक माना जाता है। बाल्यावस्था से ही इन्हें ईश्वर भक्ति में गहरी रुचि थीं। संत पीपा राजकार्य छोड़कर बनारस चले गये और वहाँ पर रामानंद के शिष्य बन गये। रामानंद ने पीपा को माया छोड़कर भक्ति करने और साधुसंतों की सेवा करने का उपदेश दिया। संत पीपा गुरु के बताये मार्ग पर चलने लगे। संत पीपा के विशेष अनुरोध पर कबीर के साथ रामानंद गागरोन आये। कुछ समय तक संत पीपा अपने गुरु के साथ रहे। संत पीपा घूम–फिरकर पुनः गागरोन आये और एक गुफा में रहने लगे। ये उच्च कोटि के संत थे। संत पीपा ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते थे। इन्होनें मूर्तिपूजा, बाह्य आडम्बरों, छूआछतू आदि का विरोध किया। संत पीपा मानते थे कि ईश्वर की दृष्टि मे सभी प्राणी समान हैं।"

32. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब विभिन्न ग्रंथों और अन्य सामग्रियों से आपत्तियों के साथ कई सामग्री विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ रखी गई थी, तो विशेषज्ञ समिति ने, जिसमें निस्संदेह विषय के विशेषज्ञ शामिल हैं, अपने विवेक से यह निर्णय लिया है कि विकल्प "(डी) गागरोन" को सही उत्तर कुंजी माना जाना चाहिए क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ गुफा स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि उसी पुस्तक में **(राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया)** पृष्ठ 532 पर, यह नीचे दिया गया है:-

"ऐतिहासिक कस्बा टोडारायसिंह में बुध सागर तालाब, पीपाजी की गुफा, सातोलाव तालाब, लल्ला पठान का किला, हाड़ी रानी का कुण्ड तथा दो कलात्मक बावड़ियाँ दर्शनीय हैं।"

33. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष एक अन्य पाठ्यपुस्तक भी प्रस्तुत की है, जिसका नाम है, प्रोफेसर पेमाराम द्वारा लिखित **राजस्थान में भक्ति आंदोलन** तथा **राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी** द्वारा प्रकाशित। उस पाठ्यपुस्तक में भी संत पीपा के संबंध में विवरण दिया गया है कि संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी (पूर्व में 1482 ईस्वी) में हुआ था तथा वे राजपूताना के गागरोन राज्य के खींची राजपूत शासक थे। पाठ में संत पीपा द्वारा यात्रा किए गए विभिन्न स्थानों के बारे में आगे विवरण दिया गया है तथा यह भी बताया गया है कि संत पीपा गागरोन वापस आए तथा फिर चले गए। इसमें यह भी उल्लेख है कि अनेक स्थानों की यात्रा के दौरान संत पीपा टोडा भी गए और अंत में वापस गागरोन आकर आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित एक गुफा में निवास करने लगे और यह स्थान उनके मंदिर, निवास और गुफा के लिए प्रसिद्ध है।

34. यह न्यायालय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय से भिन्न निर्णय पर पहुंचने के लिए विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभाएगा, विशेषकर तब जब विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया गया निर्णय प्रामाणिक पाठ पर आधारित हो, जिस पर न केवल अपीलकर्ता बल्कि प्रतिवादी दोनों निर्भर करते हैं। हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस स्थान पर संत पीपा की गुफा स्थित है, वह एक ऐतिहासिक तथ्य है और इस बात पर कोई एकमत नहीं है कि वह गुफा कहां स्थित है। निस्संदेह, अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए कुछ पाठों से संकेत मिलता है कि संत पीपा की गुफा टोडा में स्थित है, साथ ही डॉ. हुकम चंद जैन और डॉ. नारायण माली द्वारा लिखित पुस्तक **"(राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लपीडिया)"**, के अन्य प्रामाणिक पाठ से भी पता चलता है कि संत पीपा गागरोन की एक गुफा में रुके थे।

35. प्रश्न संख्या 135 से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य की सत्यता पर विचार किए बिना, जो कि मूलतः केवल विशेषज्ञों द्वारा विचार किए जाने का विषय है, न्यायालय द्वारा नहीं, विशेषकर तब जब यह 1362 से 1377 की अवधि के दौरान संत पीपा के आवागमन और प्रवास के संबंध में एक ऐतिहासिक तथ्य है, हम इन ग्रंथों के मात्र पढ़ने से पाते हैं कि संत पीपा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए और वे न केवल टोडा में रहे, बल्कि गागरोन में भी रहे। हालांकि, विभिन्न ग्रंथों में दी गई उपरोक्त प्रासंगिक जानकारी के आधार पर, जिसका दोनों पक्षों ने उल्लेख

किया है, विषय के विशेषज्ञों ने यह निर्णय लिया कि विकल्प “(डी) गागरोन” को सही उत्तर कुंजी माना जाना चाहिए।

36. हमारे विचार से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, रिट न्यायालय इस प्रश्न पर आगे विचार करने में असमर्थ है और जांच यहीं समाप्त होनी चाहिए। ऊपर उल्लिखित प्रसिद्ध निर्णयों में, यह अधिकारपूर्वक निर्धारित किया गया है कि उत्तर कुंजी की शुद्धता के संबंध में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य होगा जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, बिना किसी अनुमानात्मक तर्क प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया के और केवल दुर्लभ या अपवादात्मक मामलों में कि कोई भौतिक त्रुटि हुई है। यह भी माना गया है कि न्यायालय को किसी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट कानूनी स्थिति के रूप में स्थापित किया गया है कि न्यायालय को मुख्य उत्तरों की सत्यता को मानकर उसी धारणा के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और संदेह की स्थिति में, लाभ अभ्यर्थी के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिए।

37. उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, इसे सबसे अच्छा संदेह का मामला कहा जा सकता है और इसलिए, इसका लाभ अभ्यर्थी के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिए।

38. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

39. तदनुसार दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, भी खारिज किया जाता है।

40. इस आदेश की एक प्रति संबंधित फाइल में रखी जाए।

(शुभा मेहता),जे **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव),सीजे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।